

प्रेषक,

एन०एस०न०पल०च्यल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: ०३ जुलाई २००८

विषय:—मै० एंकर इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि० को जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार के ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल ३.३२८ है० भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या— १२५७/भूमि व्यवस्था— भू०क० दिनांक २३, नवम्बर, २००७ एवं ११४६/भूमि व्यवस्था— भू०क० दिनांक २७, दिसम्बर, २००७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० एंकर इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि० को औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(व) के अन्तर्गत तहसील हरिद्वार के ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा में गाटा /ख०सं० ६४म रकबा ०.२६६ है०, गाटा ख०सं० ६२ रकबा १.७३१ है०, गाटा /ख०सं० ६४म रकबा १.३३१ है० अर्थात् कुल रकबा ३.३२८ है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

१- केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

२- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बिन्दु सं०-११ में उल्लिखित उद्योग की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- यह स्वीकृति 180 दिनों के लिये वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 02 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।

7- सभी ऐसे डेवलपर्स द्वारा जी0आई0डी0सी0आर0 की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा इसका क्रियान्वयन का अनुश्रवण उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शारान द्वारा निर्धारित नीति/गार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान राक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)- 2005 के अनुरूप होगा।

10- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

11- कय की जाने वाली भूमि का उपयोग इकाई द्वारा प्रस्तावित इलैक्ट्रिकल वायरिंग डिवाइसेस, केबल्स एण्ड वायर्स, स्टैटिस्टिकल इनर्जी मीटर, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, फैन लैप्स, ट्यूब्स एण्ड काम्पैक्ट फ्लोरेसेन्ट लैम्पस विनिर्माणमक उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

12- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के वेशेजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत का रोजगार नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

13- भूमि कय करने के उपरान्त अर्जित भूमि को राज्य सरकार से मैगा प्राजेक्ट के लिये विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कराया जाना आवश्यक होगा।

- 14- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रस्तावित इकाई की स्थापना हेतु प्रश्नगत अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है।
- 15- किसी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।
- 16- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 17- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/ अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 18- उपरोक्त के अतिरिक्त वांछित, विधिक व अन्य औपचारिकतायें / अनुज्ञायें/ प्रमाण पत्र एवं अनापत्तियाँ इकाई स्थापना के पूर्व यथासमय प्राप्त कर ली जायेंगी।
- 19- उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
 - 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 6- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
 - 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
 - 8- श्री बी0एस0 ध्यानी, मै0 एंकर इलैक्ट्रिकल्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 1ए/1बी, सैक्टर-8बी, इन्टग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, रानीपुर, हरिद्वार।
 - 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सतोष गडोन्नी)
अनुसचिव।